इस्पातसमाचार
27 फरवरी से 4 मार्च, 2016

टाटा स्टील को रु 1,877 करोड़ के विस्तार परियोजना को अनुमति मिली

टाटा स्टील लिमिटेड को झारखण्ड में जमशेदपुर स्टील वर्क्स में अपने रु 1,877 करोड़ की विस्तार परियोजना को चलाने के लिए पर्यावरण अनुमति प्राप्त हो गई है । पर्यावरण मंत्रालय ने एक्सपर्ट अप्रेजल कमिटी (इंडस्ट्री-I) की सिफारिश के आधार पर आवेदन पर विचार किया तथा टाटा स्टील वर्क्स में कच्चे इस्पात के उत्पादन के विस्तार हेतु प्रस्ताव को पर्यावरण अनुमति स्वीकृत करने का निश्चय किया, ऐसा एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा । पर्यावरण अनुमति, जिसे कल जारी किया गया, कंपनी को दे दिया गया, बशर्ते सामान्य एवं विशिष्ट शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाय, अधिकारी ने कहा । प्रस्ताव के अनुसार टाटा स्टील कच्चे इस्पात का उत्पादन 9.7 मिलियन टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) से बढ़ाकर 11 एमटीपीए तक अपने जमशेदपुर स्टील वर्क्स में करेगा । परियोजना की कुल अनुमानित लागत है रु 1,877 करोड़ और यह वृद्धि परियोजना वर्तमान 717 हेक्टेयर के प्लांट के भीतर चालू की जायेगी और अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता नहीं होगी।

स्रोत: बिजनेश लाइन, 3 मार्च, 2016

यूएस ने भारत से इस्पात के आयात पर 266 प्रतिशत आयात ड्यूटी लगाई

भारत तथा छः अन्य देशों के उत्पादकों ने यूएस बाजार में बेठीक कम कीमतों पर कोल्ड रोल्ड स्टील को बेचा है तथा कीमतों पर 266 प्रतिशत जितना कर चार्ज किया जाएगा, ऐसा वाणिज्य विभाग ने एक प्राथमिक निर्णय में मंगलवार को कहा । सरकार ने चीन, दक्षिण कोरिया, रूस, जापान तथा यूके से आयात पर 266 प्रतिशत दरें लागू कर दी हैं, ड्यूटी के अधीन यूके भी । ब्राजील से शिपमेण्ट पर 39 प्रतिशत की पेनाल्टी लगेगी तथा दक्षिण कोरियाई उत्पादकगण 6.9 प्रतिशत कर का मुकाबला करेंगे । यह दिसम्बर से दूसरी बार है, जब यूएस सरकार ने यूएस में बेठीक कम कीमतों पर धातुओं की बिक्री के लिए विदेशी इस्पात उत्पादकों पर जुर्माना लगाया है, चायनीज मिलों सहित। न्युकॉर तथा यूएस स्टील सहित घरेलू उत्पादकों ने व्यापार मामलों को फाईल करना शुरू कर दिया है, जिसमें अनुचित अनुदान तथा अन्य गैरकानूनी व्यापार कार्यपद्धति के लिए कुछ वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों पर आरोप लगाया है।

स्रोत : फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 3 मार्च, 2016

टाटा स्टील ने टाटा डिजिटल हेल्थ सर्विस की शुरुआत की

टाटा स्टील ने टाटा मेन हॉस्पीटल, जमशेदपुर में वृहस्पतिवार को टाटा डिजिटल हेल्स सर्विसेज की शुरुआत की । यह पहल, टाटा डिजिटल हेल्थ के सहयोग से चालू की गई, जमशेदपुर में हेल्थकेयर के कायाकल्प एवं डिजिटाइज के लिए तैयार है। यह पहल टाटा समूह के कर्मचारियों एवं गैर-कर्मचारियों सहित, जमशेदपुर की समूची जनसंख्या के लिए बेहतर चिकित्सा परिणाम सुनिश्चित करेगा, टाटा हेल्थकेयर सुविधाओं के जरिये रोकथाम, अनुमानित, प्राथमिक केयर की डिलिवरी सुनिश्चित करते हुए ।

स्रोत : दि इकोनॉमिक टाइम्स, 4 मार्च,2016

ईस्पात मंत्रालय उच्च ग्रेड के आयरन ओर पर कम ड्यूटी के बारे में पूछेगा

जबकि बजट में 58 प्रतिशत एफई कंटेण्ट की अपेक्षा कम आयरन ओर पर निर्यात ड्यूटी को समाप्त कर दिया गया है, इस्पात मंत्रालय अधिक एफई कंटेण्ट वाले आयरन ओर पर भी ड्यूटी में कटौती करने हेतु वित्त मंत्रालय से कहेगा । वर्तमान में, 58 प्रतिशत से ऊपर कंटेण्ट वाले आयरन ओर पर निर्यात ड्यूटी 30 प्रतिशत है। इस्पात मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रस्तावित ड्यूटी में कटौती माइन-हेड स्टॉक को क्लीयर करने के लिए माइनरों की मदद करने के लिए नहीं की जायेगी, जो कि अभी सर्वकालीन ऊपर लगभग 150 मिलियन टन पर टिकी है, बल्कि वर्तमान उत्पादन की गति को बनाए रखने के लिए की जायेगी । आयरन ओर, दोनों लम्प, या उच्च ग्रेड तथा फाईन या घटिया ग्रेड पर निर्यात ड्यूटी, यूपीए सरकार द्वारा लगाई गई ड्यूटी को धीरे-धीरे 30 प्रतिशत तक ले जाने के पहले शून्य थी, जिसका उद्देश्य था भविष्य में इस्तेमाल के लिए देश में कच्चे माल का संरक्षण। उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाये गये निर्यात प्रतिबंध के साथ जुड़ी अधिक ड्यूटी ने निर्यातकों को 2014-15 में सिर्फ 6.12 मिट पर मुँह के बल गिरा दिया, जो 2009-10 में 117.3 मिट था। भारत देश के भीतर पर्याप्त खपत की चाहत में चीन को फाईन के रूप में अधिकांशत: आयरन ओर का निर्यात करता रहा है, जो कि सबसे अधिक खपत करने वाला देश है। चीन को निर्यात किये जाने वाले आयरन ओर में भारत का अंश 2008 में 20 प्रतिशत से 2014 में 0.5 प्रतिशत से भी कम आ गया है। सरकार ने पिछले वर्ष अप्रैल से 58 प्रतिशत से कम आयरन ओर पर निर्यात ड्यूटी में 10 प्रतिशत तक कमी कर दी है, जो कि पूर्व में 30 प्रतिशत थी । जबकि उच्च ग्रेड वाले आयरन ओर पर ड्यूटी घटाने के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का इस्पात मंत्रालय का अनुरोध घरेलू माइनरों को खुश करेगा । इस्पात मंत्रालय खुश नहीं होगा, क्योंकि इससे उनके लिए कीमतों में वृद्धि हो सकती है । यह प्रति मिट इस्पात का उत्पादन करने के लिए आम तौर पर 1.6 मिट लम्प ओर लेता है ।

स्रोत: दि फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 4 मार्च, 2016

ईयू भारत पर फेरो एलॉय टैरिफ का खतरा समाप्त

यूरोपियन यूनियन ने भारत से फेरोएलॉय पर टैरिफ लगाने का खतरा समाप्त किया, जो यूरोप में स्टील उत्पादकों के पक्ष में व्यापार उपायों की श्रृंखला में नवीनतम है। यूरोपियन कमीशन ने जॉच बन्द कर दी कि सिलिकोमैगनीज के भारतीय निर्यातक - जिसका प्रयोग आर्सेलरमित्तल तथा सैल्जगिटर एजी जैसे ईयू इस्पात निर्माताओं द्वारा किया जाता है - 28-राष्ट्र ब्लॉक में लागत के नीचे बेचा है । इस प्रैक्टिस को डंपिंग के नाम से जाना जाता है। कमीशन ने कहा कि जबकि भारत से कुछ आयात डंप किये गये थे, वे निश्चित रूप से 'मटेरियल इंज्यूरी' के कारण नहीं थे, जिसे यूरोपियन सिलीकामैगनीज उद्योग द्वारा भोगा (सफर किया) गया है। मॉडर्न इंडिया कॉन-कास्ट लि0 तथा इंडसल हायड्रो पावर एण्ड मैगनीज लि0 सहित भारतीय निर्यातक संयुक्त रूप से 23 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक का ईयू सिलीकोमैगनीज बाजार शेयर करते हैं, कमीशन ने कहा । ईयू को सिलीकोमैगनीज के अन्य विदेशी आपूर्तिकर्ता हैं नार्वे, यूक्रेन तथा दक्षिण अफ्रीका, कमीशन के अनुसार । भारत से आने वाले सिलीकोमैगनीज पर एण्टी डंपिंग ड्यूटी लगाने

के विरुद्ध निर्णय, चीन से स्टील पर अधिक एण्टी डंपिंग लेवीज लगाने की धमकी या लागू करके यूरोपियन स्टील मैन्युफैक्चरर्स के लिए प्रतियोगता पर अंकुश लगाने के ईयू के प्रयास का अनुसरण करता है ।

स्रोत : दि फाइनेंसियल एक्सप्रेस, 4 मार्च, 2016